



अमृत वाणी

अपराधी मन बिचुओं से भरा होता है।

- शेक्सपियर

संपादकीय

बढ़ते एड्स संक्रमण ने बढ़ाई चिंता

एड्स के संक्रमण को बढ़ने से रोकने किये जा रहे तमाम उपायों के बावजूद प्रतिवर्ष एड्स दिवस पर जब एड्स संक्रमित लोगों की संख्या प्रकाश में आती है तो चिंता का बढ़ना लाजिमी है। प्रतिवर्ष किए गए आकलन में ये संख्या बढ़ती ही दिखाई देती है। सच कहा जाय तो आकलन में भी सही आंकड़े सामने आ रहे हैं ऐसा मान लेना जल्दबाजी ही होगी क्योंकि लोग आसानी से अपनी पहचान उजागर नहीं करते या नहीं करना चाहते। जब हालात बिगड़ते हैं तब इलाज के लिए सामने आते हैं लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है और सर्वाधिक चिंता की बात यह होती है कि तब तक यह संक्रमण दूसरों तक फैलने की आशंका बढ़ जाती है।

जैसा कि शासकीय जानकारी में बताया गया है कि बस्तर में एड्स संक्रमितों की संख्या 2200 के पार पहुंच चुकी है। यह तो उन लोगों की संख्या है जिनकी पहचान हो पाई है। इसके अलावा न जाने पहचान छिपाने वालों की संख्या कितनी होगी। संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या की गति का अंदाजा एकीकृत परामर्श एवं परीक्षण केन्द्र की इस जानकारी से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2024 के 11 महीनों में आइ सी टी सी मोबाइल वैन से तथा गर्भवती और प्रसव वाली लगभग 15 हजार लोगों की जांच में 57 एच आइ वी पॉजिटिव पाये गए हैं।

दरअसल एड्स संक्रमण में वृद्धि की सर्वप्रमुख वजह लोगों में जागरूकता का अभाव है। अशिक्षित अज्ञानी लोगों में यह संक्रमण अधिक फैलने का कारण उनमें शारीरिक संबंधों के बारे में सतर्कता का अभाव होना है। बस्तर में ग्रामीण अक्सर रोजगार के लिए पलायन करते हैं। दूसरे प्रदेशों में दूसरे अनजान लोगों के साथ लंबे समय तक रहने के दौरान कई बार उनका ऐसा गलत संबंध स्थापित हो जाता है जिसका परिणाम वे एड्स संक्रमण के रूप में भुगतते हैं। और भी त्रासदी यह है कि इसका एहसास उन्हें शुरुआत में नहीं होता।

इसलिए यह अति आवश्यक है कि एड्स संबंधी जागरूकता कार्यक्रम को और सघन किया जाय। शहर की बजाय ग्रामीण क्षेत्रों और उन लोगों के बीच जो लोग विभिन्न कार्यों से लंबे समय के लिए घर या क्षेत्र से बाहर रहते हैं उन्हें इस बारे में सतर्क किया जाय। इसीलिए मालवाहक वाहनों के चालकों पर खास ध्यान दिए जाने की भी जरूरत है। साथ ही लोगों को पहचान छिपाने के बजाय शुरु से ही इलाज के लिए आगे आने हेतु प्रेरित किया जाना जरूरी है।



राज-काज

अडानी विवाद की संसदीय जांच की मांग

अमेरिका के न्याय मंत्रालय ने कहा है कि वहां सौर ऊर्जा संबंधी ठेके दिलवाने और उन परियोजनाओं में पैसा लगाने पर अमेरिकी निवेशकों को राजी करने के लिए अडानी ने भारतीय अधिकारियों को 25 करोड़ डॉलर की रिश्वत देने का वादा किया। उद्योगपति गौतम अडानी और उनके कारोबार पर अब बड़ा घेरा पड़ गया है। नया मामला हिंडनबर्ग रिपोर्ट जैसा नहीं है, क्योंकि इस बार अडानी और उनके उद्योग समूह से जुड़े कई प्रमुख लोगों पर अभियोग अमेरिका के न्याय मंत्रालय ने लगाया है। जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका में सौर ऊर्जा संबंधी ठेके दिलवाने और उन परियोजनाओं में पैसा लगाने पर अमेरिकी निवेशकों को राजी करने के लिए अडानी ने भारतीय अधिकारियों को 25 करोड़ डॉलर की रिश्वत देने का वादा किया। जिन पर अभियोग लगा है, उनमें गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और अडानी समूह की अक्षय ऊर्जा कंपनी के बड़े अधिकारी विनीत एस. जैन शामिल हैं। खबरों के मुताबिक अमेरिका की अदालत में पेश करने के लिए वहां के अधिकारी आरोपित व्यक्तियों के प्रत्यर्पण की मांग भारत सरकार से कर सकते हैं। भारत सरकार इस पर राजी होगी या नहीं-यह दीर्घ बात है। निर्विवाद रूप से ताजा घटना अडानी के लिए उससे कहीं बड़ा झटका है, जैसा पिछले साल उसे हिंडनबर्ग रिपोर्ट से लगा था।

राहुल गांधी को राजनीति के कुछ सबक सीखने होंगे

देश में कॉर्पोरेट विरोधी जो एकसूत्री एजेंडा राहुल ने अपनाया है, या संविधान-रक्षा एवं धर्म-निरपेक्षता के नाम पर एक सम्प्रदाय-विशेष की जो राजनीति वह कर रहे हैं, उसके सकारात्मक परिणाम नहीं आ रहे हैं, उनके इन मुद्दों के पक्ष में वोट नहीं मिले हैं। निश्चित ही राष्ट्रीय राजनीति में अगर कोई एक चीज है, जो नहीं बदली है, तो वह है भाजपा को मात देने में कांग्रेस की अक्षमता। भाजपा से सीधी टक्कर में कांग्रेस की हार का औसत प्रतिशत बढ़ता ही जा रहा है। अब तो कांग्रेस के मुद्दों से इंडिया गठबंधन के सहयोग दल ही कांग्रेस से दूरी बना रहे हैं। भाजपा जब कांग्रेस से मुकाबले में होती है तब उसका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहता है। जबकि क्षेत्रीय नेताओं के मुकाबले राहुल का जादू फीका पड़ता है। इसके उदाहरण हैं झारखंड के हेमंत सोरेन और बंगाल की ममता बनर्जी जिन्होंने उपचुनाव में सारी सीटें जीत लीं। कांग्रेस के लिये जटिल से जटिलतर होते हालातों में केरल के वायनाड में प्रियंका गांधी वाड़ा की 4.1 लाख से अधिक वोटों के अंतर से हुई भारी जीत कांग्रेस पार्टी के लिये एक उत्साहजनक संदेश हो सकता है। निश्चित रूप से प्रियंका के राजनीतिक जीवन और कांग्रेस पार्टी के लिये यह एक महत्वपूर्ण क्षण है, लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व पर लगा अक्षमता एवं अपरिपक्व राजनीति का दाग इससे कैसे कम हो सकता है?

राहुल गांधी संसद के बाहर और भीतर दोनों जगह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर पूरी तरह हमलावर रहते हैं, वे गैर-जरूरी मुद्दों को लेकर अक्सर संसद की कार्यवाही को बाधित करते हैं। अडानी एवं कॉर्पोरेट विरोधी उनका एजेंडा देश की अर्थ-व्यवस्था के लिये कितना नुकसानदायी साबित होता रहा है, देश की जनता ने इसे महसूस किया है। राहुल दस साल से यह गलती कर रहे हैं और उनकी पार्टी इसकी कीमत चुका रही है। कांग्रेस और विशेष रूप से उसके

कांग्रेस की उलटी गिनती का क्रम रूकने का नाम नहीं ले रहे हैं। महाराष्ट्र के नतीजे इसी बात को रेखांकित कर रहे हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस न तो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे पा रही है और न ही देशहित के प्रभावी मुद्दे उठा पा रही है।

नेता राहुल गांधी न जाने कब से अदाणी समूह को कोस रहे हैं। एक अमेरिकी अदालत के फैसले के बाद वह हाथ धोकर इस समूह के पीछे पड़ गए हैं, लेकिन शायद वह यह देखने से इन्कार कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल कांग्रेस के इस रवैये से सहमत नहीं हैं। विभिन्न राज्यों में जहां-जहां इंडिया गठबंधन दलों की सरकारें हैं, वे ऐसे मुद्दों से दूरी बनाना चाहते हैं। ममता बनर्जी ने जिस तरह यह कहा कि उनका दल कांग्रेस की ओर से उठाए गए किसी एक मुद्दे को प्राथमिकता नहीं देगा, उससे यही संकेत मिला कि वह नहीं चाहती कि अदाणी मामले को तूल दिया जाए। कांग्रेस को इसकी भी अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि गत दिवस ही माकपा के नेतृत्व वाली केरल सरकार ने बंदरगाह के विकास के लिए अदाणी समूह के साथ एक पूरक समझौते को अंतिम रूप दिया। साफ है कि माकपा भी अदाणी मामले में कांग्रेस के रुख से सहमत नहीं। तेलंगाना सरकार ने अदाणी समूह के साथ एक समझौता कर रखा है और अतीत में राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने भी राज्य में इस समूह के निवेश को हरी झंडी दी थी। आखिर राहुल गांधी इन स्थितियों को क्यों नहीं समझ एवं देख रहे हैं? यदि राहुल गांधी को यह लयाता है कि अदाणी समूह दामदार है तो वह अपनी सरकारों को उससे कोई नाता न रखने के लिए क्यों नहीं कह पा रहे हैं? यह समझना भी कठिन है कि कांग्रेस अमेरिकी अदालत के आकलन को अंतिम सत्य की तरह क्यों ले रही है और वह भी

जबकि इन राज्यों की डेमोग्राफी कांग्रेस के पक्ष में है, लेकिन सरकारें भाजपा की हैं। कांग्रेस मुद्दे नहीं तय कर पा रही है। बीजेपी हर राज्य के हिसाब से मुद्दे तय करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर सीट के हिसाब के मुद्दों के हिसाब से बोलते हैं। वहां के इतिहास, भूगोल, राजनीतिक परिस्थितियां सबको ध्यान में रख कर बोलते हैं। लेकिन कांग्रेस इसके हिसाब से मुद्दे और रणनीति तय नहीं कर पाती। बड़ा सवाल ये है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित दिख रही कांग्रेस इसके बाद एक भी राज्य का चुनाव क्यों नहीं जीत पाई। आखिर उसकी रणनीति में कहां खामी है और वो बार-बार कहां चूक रही है?

लगभग जीत के मुहाने पर खड़ी कांग्रेस को हरियाणा में हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के साथ यही किस्सा अब राजनीतिक तौर पर देश के दूसरे बड़े अहम राज्य महाराष्ट्र में भी दोहराया गया। झारखंड में पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुआई वाले गठबंधन में शामिल थी और वो 2019 में जीती 16 सीटों में एक भी सीट का इजाजत नहीं कर पाई। इससे पहले, जम्मू-कश्मीर के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस बुढ़ी तरह नाकाम रही। कांग्रेस 90 में से छह सीटें ही जीत पाई और नेशनल कॉंग्रेस की जूनियर पार्टनर बन कर किसी तरह अपनी नाक बचा पाई। भाजपा ने महाराष्ट्र में हिंदू मतदाताओं के रुझान का ख्याल रखा। इसी के हिसाब से नारे गढ़े। लाडकी बहिन जैसी लाभार्थी योजना, आरक्षण के सवाल और महाराष्ट्र के किसानों के मुद्दों के इर्द-गिर्द अपनी रणनीति बनाई। लेकिन राहुल गांधी ऐसे चुनावी मुद्दों को गढ़ने में क्यों असफल रहे? आखिर कांग्रेस एवं उसके नेता राहुल गांधी इन स्थितियों पर गंभीर मंथन क्यों नहीं करते?

ललित गर्ग

(वे लेखक के अपने विचार हैं)

जलवायु परिवर्तन से जूझती महिलाएं

जलवायु संकट क्षमता से अधिक संसाधनों का उपभोग और वायु प्रदूषण ने जिन समस्याओं को जन्म दिया है उनका सबसे अधिक सामना महिलाओं को ही करना पड़ रहा है। प्रेगनेंसी के पहले और आखिरी महीने में महिलाओं एवं गर्भवती शिशु को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। संयुक्त राष्ट्र की ओर से हाल ही में महिला आधारित एक रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2050 तक जलवायु परिवर्तन के चलते 158 मिलियन से अधिक महिलाएं और लड़कियां गर्बी की ओर जा सकती हैं। वहीं 236 मिलियन से अधिक महिलाओं और लड़कियों को खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ सकता है। एक अनुमान के अनुसार दुनिया भर में हर साल 130 मिलियन लड़कियों को शिक्षा के मानवाधिकार से वंचित रखा जाता है और जलवायु संबंधी संकट इस दिक्रत को और अधिक बढ़ा देते हैं। ऐसे मुश्किल समय में लड़कियों की जल्दी शादी होने की संभावना अधिक होती है क्योंकि उन्हें घर की जरूरतों में मदद करने के लिए सबसे पहले स्कूल से निकाला जाता है। जलवायु संकट क्षमता से अधिक संसाधनों का उपभोग और अथाह वायु प्रदूषण ने जिन

समस्याओं को जन्म दिया है उनका सबसे अधिक सामना महिलाओं को ही करना पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन और बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते पूरी दुनिया में मां की कोख में पल रहे शिशु भी सुरक्षित नहीं है। डॉक्टरों का कहना है कि हवा में बिखरे हैंवी मेटलस की की सांस के जरिए अजन्मे बच्चों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वायु प्रदूषण नवजातों के दिल, दिमाग और फेफड़ों के लिए घातक है। प्रदूषित वातावरण में सांस लेने पर पॉल्यूशन प्लेसेंटा को पार कर भ्रूण तक पहुंच रहा है। प्रदूषण खून के जरिए पोषक तत्वों को शिशु तक पहुंचने से रोकता है। इससे शिशु के दिमाग और फेफड़े सही से डेवलप नहीं हो पाते हैं। बच्चों में हार्ट में परेशानीएं और की जन्मजात बीमारीएं न्यूरो डेवलपमेंट पर दुष्प्रभाव एवं लिंग की मैच्योरिटी पर भी असर होता है। कई बच्चों में ऑटिज्म और बौद्धिक दिव्यांगता की भी समस्या देखी गई है। चिंता की बात यह है कि गर्भवती महिलाओं की शुरुआती जांच में ही भ्रूण में प्रदूषण के कण मिल रहे हैं। लंबे समय तक अगर बच्चा इस प्रदूषण के संपर्क में रहता है तो उसे कैंसर होने का खतरा भी बना रहता है। चीन के गुआंगडोंग प्रांत में प्रदूषण से होने वाली प्रीमैच्योर डिलीवरी को लेकर एक शोध हुआ। इसमें शामिल 687 महिलाओं को प्रीमैच्योर डिलीवरी हुई थी और 1097 महिलाओं को कम वजन वाले बच्चे हुए थे। उनकी तुलना 1766 हेल्दी बर्थ वाली महिलाओं के साथ की गई। गौर करने वाली बात यह है कि चीन के इस प्रांत में पूरे देश के औसत से कम प्रदूषण होता है। चीन में भी उत्तर भारत की तरह सितंबर-अक्टूबर से वायु प्रदूषण बढ़ना शुरू होता है और गर्मियों में

कम होता है। इस शोध में यह पता चला कि प्रेगनेंसी के पहले और आखिरी महीने में महिलाओं तथा गर्भवती शिशु को प्रदूषण से सबसे ज्यादा नुकसान होता है। वहीं अमेरिका में होने वाले कुल प्रीमैच्योर बर्थ में तीन फीसदी की वजह प्रदूषण होता है। ऐसे बच्चों की संख्या 16 हजार है। प्लोस मैगजीन के मुताबिक दुनिया भर में करीब 60 लाख बच्चे प्रदूषण की वजह से समय से पहले जन्म ले रहे हैं। इनमें से आधे बच्चे अंडरवेट यानी कम वजन के हैं। वहीं लैसट की ओर से भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में वायु प्रदूषण के प्रेगनेंसी पर असर को लेकर एक स्टडी की गई थी। इसमें सामने आया कि तीनों देशों में प्रदूषण की वजह 29 प्रतिशत प्रेगनेंसी लॉस यानी गर्भपात हुआ। इसमें से अकेले 77 प्रतिशत प्रेगनेंसी लॉस भारत में हुआ, जबकि पाकिस्तान में 12 प्रतिशत और बांग्लादेश में 11 प्रतिशत मामले सामने आए। इस स्टडी में 34,197 महिलाओं को शामिल किया गया था। जिनमें से 27,480 महिलाओं ने मिसकैरेज और 6,717 स्टिल बर्थ, बच्चे की हार्ट बीट गायब होना डेड फेटस। शोध में कहा गया कि प्रदूषण बढ़ने के साथ मानव स्वास्थ्य का खतरा भी बढ़ गया है। आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि वायु प्रदूषण महिला स्वास्थ्य के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बाहरी खतरा बना हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि एचआईवी-एड्स मलेरिया और टीबी के लिए हर साल बड़े वैश्विक कोष का निवेश किया जाता है लेकिन वायु प्रदूषण के लिए कोई ऐसा नहीं है।

-अमित बैजनाथ

(वे लेखक के अपने विचार हैं)

भाजपा ने दांव बहुत कायदे से आजमाया

हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों राज्यों के चुनाव नतीजे हैरान करने वाले थे। दोनों राज्यों में सामान्य समझ यह कह रही थी कि भाजपा का गठबंधन चुनाव हार रहा है। तमाम पत्रकार, सर्वेक्षण करने वाली एजेंसियां, राजनीतिक विश्लेषक और पार्टियों के नेता भी यह मान रहे थे कि दोनों राज्यों में भाजपा के खिलाफ माहौल है। पांच महीने पहले दोनों राज्यों में लोकसभा चुनाव में भाजपा को झटका लगा था। महाराष्ट्र में उसकी सीटें 23 से घट कर नौ और हरियाणा में 10 से घट कर पांच रह गई थीं। हरियाणा में तो सत्ता विरोधी लहर को कम करने के लिए भाजपा ने साढ़े नौ साल मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर को हटा दिया था और उनकी जगह नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया था। हालांकि उन सैनी की इच्छा के विपरीत उनकी विधानसभा सीट बदल दी गई थी। वे चुनाव जीतने के लेकर कई कर्तई आशावाचित नहीं थे। तभी आठ अक्टूबर को वोटों की गिनती के दौरान शुरुआती रुझानों में जब भाजपा बहुत पिछड़ गई तो उन्होंने सामने आकर हार स्वीकार कर ली और कहा कि अगर भाजपा हारती है तो उसकी जिम्मेदारी उनकी होगी, पार्टी आलाकमान की नहीं होगी। लेकिन उसके चंद मिनटों के बाद ही सारी तस्वीर बदल गई और भाजपा ने बड़ी जीत हासिल कर ली। हरियाणा में चुनाव नतीजों के बाद कहा गया कि पिछड़ी जाति के नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाना भाजपा का मास्टरस्ट्रोक था, जिससे 36 फीसदी पिछड़ी जातियां एकजुट हो गईं और भाजपा जीत गई। यही तर्क महाराष्ट्र की आश्चर्यजनक जीत के पीछे भी दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि भाजपा ने मराठा ध्वविकरण के मुकाबले पिछड़ी जातियों को एकजुट किया। इसके लिए सरकारी स्तर पर भी प्रयास किए गए और राजनीतिक स्तर पर भी।

अजीत द्विवेदी

(वे लेखक के अपने विचार हैं)

कर्ग पहली 5571					
1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24

कर्ग पहली 5570 का हल					
1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42
43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54
55	56	57	58	59	60

सुडोकू पहली क्रमांक- 5571					
1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42
43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54
55	56	57	58	59	60

सुडोकू पहली क्र. 5570					
1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42
43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54
55	56	57	58	59	60